



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3065]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941

No. 3065]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

का.आ. 3350(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2019 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में,-
(i) पैरा 13 में,-

क) उप-पैरा (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु बोर्ड द्वारा नामित निदेशक एक वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि बोर्ड का यह विचार हो कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण बैंक के समुचित प्रबंधन के हित में इस प्रकार नामित किसी निदेशक को एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी पद पर बनाए रखना आवश्यक है तो बोर्ड जैसा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे निदेशक को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए या, जो एकबार में छह माह से अधिक न हो, तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकता है; तथापि, इस प्रकार की कुल अतिरिक्त अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।”,

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण को रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘स्पष्टीकरण’ – उप-पैरा (2) के प्रयोजन हेतु ‘कार्यपालक निदेशक’ से पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं और न ही उन्हें ऐसा नामनिर्दिष्ट किया गया है।”;

(ii) पैरा 13क में,-

(क) उप-पैरा (2) में “उप-खंड (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

“उप-पैरा (1)”;

(ख) उप-पैरा (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(3क) उप-पैरा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उन बैंकों में, जिनकी निवल अनर्जक आस्ति जोखिम भारित आस्ति के छह प्रतिशत से कम हो, ऋण अनुमोदन समिति निम्नलिखित ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी-

(क) दस लाख करोड़ रुपए से अधिक कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले में आठ सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या

(ख) पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक और दस लाख करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले से छह सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या

(ग) तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक और पांच लाख करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले से पांच सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या

(घ) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में दो सौ पचास करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा के प्रयोजन हेतु निवल अनर्जक आस्ति, जोखिम भारित आस्ति और कुल कारोबार का परिकलन बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार किया जाएगा और ‘कुल कारोबार’ अभिव्यक्ति का अर्थ बैंक का समग्र ऋण तथा अग्रिम और कुल जमाराशि का योग है।”

(ग) उप-पैरा (4) में “उप-खंड (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

“उप-पैरा (3)”;

(घ) उप-पैरा (8) में, दोनों स्थानों पर ‘खंड’ शब्द, के स्थान पर जहां कहीं उनका प्रयोग किया गया है, ‘पैरा’ शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. 16/22/2019-बीओ-I]

मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3793(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:-

क्रम सं.	का.आ. सं.	तारीख
1.	2.	3.
1.	का.आ. 67 (अ)	17.11.1971
2.	का.आ. 192 (अ)	15.3.1972
3.	का.आ. 575 (अ)	4.9.1972
4.	का.आ. 651 (अ)	25.9.1972
5.	का.आ. 715 (अ)	16.11.1972

6.	का.आ. 3467 (अ)	5.12.1973
7.	का.आ. 1992 (अ)	16.6.1975
8.	का.आ. 1088 (अ)	18.2.1976
9.	का.आ. 421 (अ)	21.6.1976
10.	का.आ. 888 (अ)	11.11.1980
11.	का.आ. 346 (अ)	30.4.1983
12.	का.आ. 144 (अ)	1.3.1984
13.	का.आ. 368 (अ)	27.4.1985
14.	का.आ. 559 (अ)	30.7.1985
15.	का.आ. 783 (अ)	25.10.1985
16.	का.आ. 922 (अ)	30.12.1985
17.	का.आ. 417 (अ)	11.7.1986
18.	का.आ. 1234 (अ)	30.12.1988
19.	का.आ. 809 (अ)	1.11.1992
20.	का.आ. 289 (अ)	3.4.1995
21.	का.आ. 907 (अ)	10.11.1995
22.	का.आ. 507 (अ)	5.2.1996
23.	का.आ. 58 (अ)	20.1.2000
24.	का.आ. 934 (अ)	17.10.2000
25.	का.आ. 1172 (अ)	29.12.2000
26.	का.आ. 197 (अ)	2.3.2001
27.	का.आ. 251 (अ)	19.2.2007
28.	का.आ. 334 (अ)	8.3.2007
29.	का.आ. 1057 (अ)	29.6.2007
30.	का.आ. 2695 (अ)	19.11.2008
31.	का.आ. 2383 (अ)	15.9.2009
32.	का.आ. 2736 (अ)	5.12.2011
33.	का.आ. 2749 (अ)	19.11.2012
34.	का.आ. 42 (अ)	17.12.2014
35.	का.आ. 348 (अ)	4.2.2015
36.	का.आ. 1836 (अ)	7.7.2015
37.	का.आ. 1216 (अ)	23.3.2016

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2019

S.O. 3350(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,—
 - (i) in paragraph 13,—
 - (A) in sub-paragraph (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that the Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year:

Provided further that in case the Board is of the opinion that circumstances exist which necessitate in the interest of proper management of the bank, continuation of a Director so nominated beyond the period of one year, the Board may permit such Director to continue to hold office for such further period or periods not exceeding six months at a time, as it may specify; so, however, that the total duration of such further period shall not exceed one year.”;
 - (B) for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely:—

“*Explanation.*— For the purposes of sub-paragraph (2), “Executive Director” means the whole-time Director, not being the Managing Director and Chief Executive Officer appointed under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Act and designated as such.”;
 - (ii) in paragraph 13A,—
 - (A) in sub-paragraph (2), for the word, brackets and figure “sub-clause (1)”, the following shall be substituted, namely:—

“sub-paragraph (1)”;
 - (B) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (3), in banks with net non-performing assets of less than six per cent. of risk-weighted assets, the Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals—

 - (a) up to eight hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than ten lakh crore rupees; or
 - (b) up to six hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than five lakh crore rupees and up to ten lakh crore rupees; or
 - (c) up to five hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than three lakh crore rupees and up to five lakh crore rupees; or
 - (d) up to two hundred fifty crore rupees, in case of other nationalised banks.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph, net non-performing assets, risk weighted assets and total business shall be reckoned as per the last declared results of the bank, and the expression "total business" means the summation of the gross loans and advances and the total deposits of the bank.";

(C) in sub-paragraph (4), for the word, brackets and figure “sub-clause (3)”, the following shall be substituted, namely:—

“sub-paragraph (3)”;

(D) in sub-paragraph (8), for the word “clause” at both places where they occur, the word “paragraph” shall be substituted.”.

[F. No. 16/22/2019-BO.I]

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal scheme was published *vide* notification number S.O. 3793(E), dated the 16th November, 1970 and subsequently amended *vide* following notifications:—

S. No.	S.O. No.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	S.O. 67 (E)	17.11.1971
2.	S.O. 192 (E)	15.3.1972
3.	S.O. 575 (E)	4.9.1972
4.	S.O. 651 (E)	25.9.1972
5.	S.O. 715 (E)	16.11.1972
6.	S.O. 3467 (E)	5.12.1973
7.	S.O. 1992 (E)	16.6.1975
8.	S.O. 1088 (E)	18.2.1976
9.	S.O. 421 (E)	21.6.1976
10.	S.O. 888 (E)	11.11.1980
11.	S.O. 346 (E)	30.4.1983
12.	S.O. 144 (E)	1.3.1984
13.	S.O. 368 (E)	27.4.1985
14.	S.O. 559 (E)	30.7.1985
15.	S.O. 783 (E)	25.10.1985
16.	S.O. 922 (E)	30.12.1985
17.	S.O. 417 (E)	11.7.1986
18.	S.O. 1234 (E)	30.12.1988
19.	S.O. 809 (E)	1.11.1992
20.	S.O. 289 (E)	3.4.1995
21.	S.O. 907 (E)	10.11.1995
22.	S.O. 507 (E)	5.2.1996
23.	S.O. 58 (E)	20.1.2000
24.	S.O. 934 (E)	17.10.2000

25.	S.O. 1172 (E)	29.12.2000
26.	S.O. 197 (E)	2.3.2001
27.	S.O. 251 (E)	19.2.2007
28.	S.O. 334 (E)	8.3.2007
29.	S.O. 1057 (E)	29.6.2007
30.	S.O. 2695 (E)	19.11.2008
31.	S.O. 2383 (E)	15.9.2009
32.	S.O. 2736 (E)	5.12.2011
33.	S.O. 2749 (E)	19.11.2012
34.	S.O. 42 (E)	17.12.2014
35.	S.O. 348 (E)	4.2.2015
36.	S.O. 1836 (E)	7.7.2015
37.	S.O. 1216 (E)	23.3.2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

का.आ. 3351(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में,-

(i) पैरा 13 में,-

(क) उप-पैरा (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु बोर्ड द्वारा नामित निदेशक एक वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि बोर्ड का यह विचार हो कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण बैंक के समुचित प्रबंधन के हित में इस प्रकार नामित किसी निदेशक को एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी पद पर बनाए रखना आवश्यक है तो बोर्ड जैसा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे निदेशक को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए या, जो एकबार में छह माह से अधिक न हो, तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकता है; तथापि, इस प्रकार की कुल अतिरिक्त अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण – उप-पैरा (2) के प्रयोजन हेतु ‘कार्यपालक निदेशक’ से पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं और न ही उन्हें ऐसा नामनिर्दिष्ट किया गया है।”

(ii) पैरा 13 में,-

(क) उप-पैरा (2) में “उप-खंड (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“उप-पैरा (1)”;

- (ख) उप-पैरा (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- “(3क) उप-पैरा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उन बैंकों में, जिनकी निवल अनर्जक आस्ति जोखिम भारित आस्ति के छह प्रतिशत से कम हो, ऋण अनुमोदन समिति निम्नलिखित ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी-
- (क) दस लाख करोड़ रुपए से अधिक कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले में आठ सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या
- (ख) पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक और दस लाख करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले से छह सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या
- (ग) तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक और पांच लाख करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले से पांच सौ करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव; या
- (घ) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में दो सौ पचास करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव।
- स्पष्टीकरण:** इस उप-पैरा के प्रयोजन हेतु निवल अनर्जक आस्ति, जोखिम भारित आस्ति और कुल कारोबार का परिकलन बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार किया जाएगा और ‘कुल कारोबार’ अभिव्यक्ति का अर्थ बैंक का समग्र ऋण तथा अग्रिम और कुल जमाराशि का योग है।”
- (ग) उप-पैरा (4) में “उप-खंड (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-
- “उप-पैरा (3)”;
- (घ) उप-पैरा (8) में, दोनों स्थानों पर ‘खंड’ शब्द, के स्थान पर जहां कहीं उनका प्रयोग किया गया है, ‘पैरा’ शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 16/22/2019-बीओ-I]

मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 875(अ), तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:-

क्रम सं.	का.आ. सं.	तारीख
1.	2.	3.
1.	का.आ. 345 (अ)	30.4.1983
2.	का.आ. 145 (अ)	1.3.1984
3.	का.आ. 369 (अ)	27.4.1985
4.	का.आ. 560 (अ)	30.7.1985
5.	का.आ. 784 (अ)	25.10.1985
6.	का.आ. 923 (अ)	30.12.1985
7.	का.आ. 418 (अ)	11.7.1986
8.	का.आ. 1235 (अ)	30.12.1988
9.	का.आ. 810 (अ)	1.11.1992
10.	का.आ. 290 (अ)	3.4.1995
11.	का.आ. 908 (अ)	10.11.1995
12.	का.आ. 508 (अ)	5.2.1996

13.	का.आ. 59 (अ)	20.1.2000
14.	का.आ. 934 (अ)	17.10.2000
15.	का.आ. 1173 (अ)	29.12.2000
16.	का.आ. 198 (अ)	2.3.2001
17.	का.आ. 252 (अ)	19.2.2007
18.	का.आ. 335 (अ)	8.3.2007
19.	का.आ. 1058 (अ)	29.6.2007
20.	का.आ. 2696 (अ)	19.11.2008
21.	का.आ. 2384 (अ)	15.9.2009
22.	का.आ. 2737 (अ)	5.12.2011
23.	का.आ. 2750 (अ)	19.11.2012
24.	का.आ. 43 (अ)	17.12.2014
25.	का.आ. 349 (अ)	4.2.2015
26.	का.आ. 1837 (अ)	7.7.2015
27.	का.आ. 1215 (अ)	23.3.2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2019

S.O. 3351(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,—
 - (i) in paragraph 13,—
 - (A) in sub-paragraph (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that the Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year:

Provided further that in case the Board is of the opinion that circumstances exist which necessitate in the interest of proper management of the bank, continuation of a Director so nominated beyond the period of one year, the Board may permit such Director to continue to hold office for such further period or periods not exceeding six months at a time, as it may specify; so, however, that the total duration of such further period shall not exceed one year.”;
 - (B) for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely:—

“Explanation.— For the purposes of sub-paragraph (2), “Executive Director” means the whole-time Director, not being the Managing Director and Chief Executive

Officer appointed under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Act and designated as such.”;

(ii) in paragraph 13A,—

(A) in sub-paragraph (2), for the word, brackets and figure “sub-clause (1)”, the following shall be substituted, namely:—

“sub-paragraph (1)”;

(B) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (3), in banks with net non-performing assets of less than six per cent. of risk-weighted assets, the Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals—

(a) up to eight hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than ten lakh crore rupees; or

(b) up to six hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than five lakh crore rupees and up to ten lakh crore rupees; or

(c) up to five hundred crore rupees, in case of banks having total business of more than three lakh crore rupees and up to five lakh crore rupees; or

(d) up to two hundred fifty crore rupees, in case of other nationalised banks.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph, net non-performing assets, risk weighted assets and total business shall be reckoned as per the last declared results of the bank, and the expression “total business” means the summation of the gross loans and advances and the total deposits of the bank.”;

(C) in sub-paragraph (4), for the word, brackets and figure “sub-clause (3)”, the following shall be substituted, namely:—

“sub-paragraph (3)”;

(D) in sub-paragraph (8), for the word “clause” at both places where they occur, the word “paragraph” shall be substituted.”.

[F. No. 16/22/2019-BO.I]

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal scheme was published vide notification number S.O. 875(E), dated the 4th November, 1980 and subsequently amended *vide* following notifications:—

Sl. No.	S.O. No	Date
(1)	(2)	(3)
1.	S.O. 345 (E)	30.4.1983
2.	S.O. 145 (E)	1.3.1984
3.	S.O. 369 (E)	27.4.1985
4.	S.O. 560 (E)	30.7.1985
5.	S.O. 784 (E)	25.10.1985
6.	S.O. 923 (E)	30.12.1985
7.	S.O. 418 (E)	11.7.1986

8.	S.O. 1235 (E)	30.12.1988
9.	S.O. 810 (E)	1.11.1992
10.	S.O. 290 (E)	3.4.1995
11.	S.O. 908 (E)	10.11.1995
12.	S.O. 508 (E)	5.2.1996
13.	S.O. 59 (E)	20.1.2000
14.	S.O. 934 (E)	17.10.2000
15.	S.O. 1173 (E)	29.12.2000
16.	S.O. 198 (E)	2.3.2001
17.	S.O. 252 (E)	19.2.2007
18.	S.O. 335 (E)	8.3.2007
19.	S.O. 1058 (E)	29.6.2007
20.	S.O. 2696 (E)	19.11.2008
21.	S.O. 2384 (E)	15.9.2009
22.	S.O. 2737 (E)	5.12.2011
23.	S.O. 2750 (E)	19.11.2012
24.	S.O. 43(E)	17.12.2014
25.	S.O. 349(E)	4.2.2015
26.	S.O. 1837 (E)	7.7.2015
27.	S.O. 1215 (E)	23.3.2016
